# पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International Since 1983

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 27 , अंक 2/2026

### हम राजस्थानी टूरिज्म यील्ड पर देना होगा ध्यान

## विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पिछड़ रहा राजस्थान

भारत आज पर्यटन के क्षेत्र में एक अहम मोड़ पर खड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने 160 से अधिक देशों के लिए ई-वीजा सुविधा शुरू कर विदेशी पर्यटकों के लिए रास्ता आसान किया है। लेकिन अब जब दुनियाभर में पर्यटन वापस तेजी से पटरी पर आ रहा है और देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है तो केवल छोटे-छोटे सुधार काफी नहीं होंगे। अब जरूरत है वीजा नीति को एक मजबूत आर्थिक रणनीति के रूप में अपनाने की ताकि सिर्फ पर्यटकों की संख्या ही न बढ़े, बल्कि ऐसे पर्यटक आएं जो ज्यादा खर्च करें और अर्थव्यवस्था को मजबूती दें।

वैश्विक आंकड़े बताते है कि वीजा नियमों में ढील देने से पर्यटन पर सीधा असर पड़ता है। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार, वीजा सुविधा आसान होने से अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 5 से 25 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। खासकर तब, जब 2024 में वैश्विक पर्यटन 1.4 अरब के आंकड़े को पार कर चुका है और महामारी से पहले के स्तर पर लौट आया है।

इसके बावजूद भारत अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। देश मे हर साल लगभग 2 से 2.2 करोड़ विदेशी पर्यटक आते हैं, जिससे 28 से 35 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। ये आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन दुनिया के शीर्ष पर्यटन देशों की तुलना में अभी भी कम है। विश्व आर्थिक मंच की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत पर्यटन विकास सूचकांक में 39वें स्थान पर है। इसका अर्थ है कि अभी भी अंतरराष्ट्रीय खुलापन, बुनियादी ढांचा और पर्यटन सेवाओं में सुधार की जरूरत है। अगर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से तुलना करें तो अंतर साफ दिखता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों ने वीजा फ्री एंट्री और वीजा-ऑन-अराइवल जैसी नीतियों को तेजी से लागू किया है। साथ ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आकर्षक पर्यटन अनुभव भी विकसित किए हैं।

इसी का नतीजा है कि थाईलैंड जैसे देश हर साल 3.5 से 4 करोड़ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो भारत से कहीं ज्यादा है। उनकी सफलता का राज है-आसान प्रवेश और बेहतर अनुभव। भारत में अभी भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। ई-वीजा प्रक्रिया आसान हुई है, लेकिन वीजा-फ्री सुविधा सीमित है, वीजा की अवधि कम होती है और मल्टी-एंट्री विकल्प भी कम है। ये छोटी लगने वाली बातें बड़े खर्च करने वाले पर्यटकों के फैसलों को प्रभावित करती हैं।

इसका असर राज्यों में भी दिखता है। राजस्थान जैसे प्रमुख पर्यटन राज्य में टूरिज्म से राज्य की जीडीपी का लगभग 12 प्रतिशत आता है, लेकिन विदेशी पर्यटकों की संख्या केवल 15 से 20 लाख है। यानी अमारे यहां पर्यटन का विकास घरेलू पर्यटकों पर ज्यादा आधारित है। जबकि विदेशी पर्यटक घरेलू पर्यटकों की तुलना में 2 से 4 गुना ज्यादा खर्च करते हैं और ज्यादा समय तक रुकते हैं। इसे 'टूरिज्म यील्ड' कहा जाता है, यानी प्रति पर्यटक होने वाली कमाई। दुनिया के सफल देश इसी पर ध्यान देते हैं-कम पर्यटक नहीं, बल्कि ज्यादा खर्च करने वाले पर्यटक। अगर भारत वीजा नियमों को और आसान बनाता है और विदेशी पर्यटकों की संख्या में सिर्फ 10-15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो इससे होने वाली कमाई में बड़ा इजाफा हो सकता है।

भारत ने बुनियादी ढांचा और वीजा प्रणाली में सुधार की शुरुआत कर दी है। अब जरूरत है एक ठोस रणनीति की जैसे ज्यादा देशों के लिए वीजा-फ्री सुविधा, लंबी अवधि के लिए वीजा और मल्टी-एंट्री विकल्प। आज के समय में वही देश आगे बढ़ेंगे, जहां पहुंचना आसान हो और अनुभव बेहतर हो। भारत के पास संस्कृति, प्रकृति और विविधता की कोई कमी नहीं है। अब जरूरत है एक ऐसी वीजा नीति की,जो पर्यटन को सिर्फ प्रक्रिया नहीं बल्कि आर्थिक विकास का मजबूत साधन बनाए।

**प्रदीप एस महता**
महामंत्री, कट्स इंटरनेशनल

### इस अंक में...

- बंजर जमीन ही घोटाले की गवाह ........... 3
- इलाज 25 से 96 फीसदी हुआ महंगा ....... 4
- विश्व में अनिश्चितता, भारत विकास पथ पर . 7
- प्रसारण में विद्युत क्षति जनता पर भारी ...... 8
- मानसून से पहले बांधों की 'हेल्थ चेक' ..... 9

## जनजातीय क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर

# प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए सामूहिक भागीदारी आवश्यक

कॉमन वेल्थ फाऊंडेशन के सहयोग से 'कट्स' द्वारा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में संचालित परियोजना के तहत 4 जून को प्रतापगढ़ स्थित होटल क्राउन लीला सभागार में राज्य स्तरीय प्रसार बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए संयुक्त निदेशक एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम तथा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के नोडल अधिकारी डॉ. एस.एन. धौलपुरिया ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल देते हुए टीबी मुक्त एवं तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत अभियान को गति देने के लिए सभी को प्रेरित किया।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ. नरेंद्र सिंह ने तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणामों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी को नशे की लत से बचाकर स्वस्थ समाज की स्थापना करना समय की आवश्यकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जीवराज मीणा ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र तक स्वास्थ्य सुविधाए पहुंचाने के लिए जिले में सुव्यवस्थित व्यवस्था संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन की आसान पहुंच में लाने के लिए जन सहयोग एवं जनभागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है।

बांसवाड़ा के जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार भाभोर ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष जोर देते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं को नियमित जांच एवं बच्चों को शत-प्रतिशत टीकाकरण के लिए महिलाओं को जागरूक होकर आगे आने की आवश्यकता है। महिला एवं बाल विकास के उप निदेशक करण सिंह डामोर ने बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाली सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। बैठक के प्रारंभ में 'कट्स' जयपुर के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी अमरदीप सिंह ने स्वागत उद्बोधन के दौरान परियोजना की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन की आसान पहुंच एवं जन भागीदारी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह परियोजना संचालित की जा रही है।

'कट्स' बांसवाड़ा के जिला प्रबंधक मदनलाल कीर ने परियोजना गतिविधियों एवं आगामी कार्य योजना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले की 100 ग्राम पंचायतों में जागरूकता बैठकें, नागरिक निरीक्षण समितियों की आमुखीकर एवं द्विपक्षीय परिचर्चा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार ओझा, गणेशलाल डामोर, मालीराम, ऐजन बाई एवं धौली बाई सहित विभिन्न वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, भरतपुर, भीलवाड़ा एवं उदयपुर की स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय एवं जिलास्तरीय अधिकारी तथा महिला-पुरुष अधिकारियों सहित कुल 86 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

# बैंकिंग व साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जमाकर्ता हो रहे जागरूक

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं 'कट्स' जयपुर के सहयोग से अजमेर जिले के हिंगोनिया गांव में आयोजित जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड अधिकारी के.एन. वर्मा ने कहा है कि बैंकिंग फ्रॉड, साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए हम सभी को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने बैंकिंग प्रक्रिया के अतंर्गत आपातकालीन वित्तीय सुविधा, आय की सुरक्षा व सुनिश्चितता, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और बैंक में अंतर, राशि हस्तांतरण विधियां व डिजिटल लेन-देन जैसी कई उपयोगी जानकारियां दी।

विकासोन्मुख संस्थान के सचिव राजेश मालाकार ने कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी एवं 'कट्स' जयपुर के राजदीप पारीक ने संभागियों को जमाकर्ता शिक्षा से संबंधित योजनाओं एवं जमाकर्ता के अधिकारों के बारे में बताया। बैंक ऑफ इंडिया केकड़ी शाखा के प्रबंधक नरेन्द्र चौधरी ने संभागियों को बैंक में खाता खोलने, विभिन्न जमा योजनाओं से होने वाले लाभों और जमाकर्ता के अधिकारों की जानकारी दी। वन स्टॉप सखी सेंटर की टीना शर्मा तथा दीपांशी ने फ्रॉड के बाद होने वाली कार्यवाही के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में करीब 50 संभागियों की सक्रिय भागीदारी रही।

## बजट चवन्नी खर्चा रुपया...

राजस्थान के जनजाति छात्रावासों में खाद्य सामग्री की खरीद को लेकर बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। नियमों में स्पष्ट 10 हजार रुपए की सीमा के बावजूद वार्डनों ने करोड़ों रुपए की खरीद कर डाली। चौंकाने वाली बात यह है कि जुलाई 2025 से मार्च 2026 के बीच करीब 70 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए।

इस खर्च के लिए न तो टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई और न ही किसी स्तर पर जांच या सत्यापन हुआ। प्रदेश के 376 छात्रावासों में बड़े पैमाने पर यह खाद्य सामग्री खरीदी गई। गंभीर सवाल यह है कि यह खरीद किस प्रक्रिया के तहत हुई, इसका जवाब अधिकारियों के पास भी नहीं है। जब अलग अलग छात्रावासों के बिलों की जांच की गई तो उनमें भारी विसंगतियां निकली। सरकार ने बाद में पारदर्शिता के लिए टेंडर निकाले, लेकिन पूरे राजस्थान में सिर्फ एक ही फर्म सामने आई। *(रा.प., 22.04.26)*

## गरीब परिवारों के हक पर डाका

प्रदेश में 33 जिलों की 473 डीलर समितियों ने गरीब परिवारों के हक का 59 लाख किलो गेहूं बाजार में बेच खाया। इन गरीब परिवारों की रसोई राशन की दुकान पर मिलने वाले इस गेहूं से चलती है। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से यह गेहूं गरीबों को बांटा जाना था।

गरीबों के इस गेहूं का गबन करने मे टॉप फाइव जिलों में बांसवाड़ा, बारां, कोटा, अलवर, और सिरोही हैं। पीडीएस अधिकारियों के अनुसार अधिकांश मामलों में फर्जी वितरण, रिकॉर्ड में हेराफेरी, लाभार्थियों के नाम पर फर्जी उठाव, स्टॉक में गड़बड़ी और खुले बाजार में गेहूं बेचने जैसी अनियमितताएं सामने आई हैं। अब विभाग ने प्रदेश के हर जिला रसद कार्यालय में वसूली शाखा बनाने का आदेश जारी किया है। *(दै.भा., 13.06.26)*

## सीएजी का बड़ा सवाल...

राज्य की वित्तीय स्थिति पर अब सख्त निगरानी शुरू हो गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) के कारण अगले 10 साल में खजाने पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का सालाना ब्यौरा और ओपीएस लागू करने के फैसले की पूरी रिपोर्ट मांगी है।

कैग ने यह जानकारी वित्त विभाग के एसीएस से निर्धारित फार्मेट में भेजने को पत्र लिखा है। यह पूरी प्रक्रिया जवाबदेही से जुड़े प्रावधानों के तहत की जा रही है। गौरतलब है कि सरकार से यह जानकारी मिलने के बाद कैग सभी आंकड़ों की विस्तृत ऑडिट करेगा। यदि किसी तरह की वित्तीय गड़बड़ी या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उसे ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। कैग की यह रिपोर्ट विधानसभा में पेश होती है और जनलेखा समिति मामलों की जांच कार्रवाई की सिफारिश करती है।

*(दै.भा., 26.04.26)*

# बंजर जमीन ही घोटाले की गवाह

जंगल बचाने के नाम पर सरकारी खजाने को लूटने का काम वन विभाग के अधिकारी ही कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 में धौलपुर के सर मथुरा क्षेत्र में वन विकास के नाम पर 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें गड्ढे खोदने, पौधे लगाने, बीज खरीदने ट्रेंच खोदने के काम होने थे। अफसरों ने आधा काम पूरा कर पूरे पैसे उठा लिए।

ग्राउंड पर चैक किया तो एक भी पौधा नहीं दिखा। बंजर पहाड़ी जमीन पूरे घोटाले की कहानी कह रही है। उदाहरण के तौर पर 87 लाख 57 हजार खर्च कर 3.25 लाख गड्ढे खोदे गए, लेकिन मौके पर काम मात्र डेढ़ लाख रुपए का ही किया गया। इस प्रकार स्ट्रेंच खुदाई और पौधारोपण में भी एक करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया गया। कुल मिलाकर 5 करोड़ 80 लाख रुपए अफसरों की जेब में चले गए । इसका खुलासा सीसीएफ पी.कैथिरवेल की जांच रिपोर्ट में हुआ है। *(दै.भा., 26.04.26)*

## फर्जी हस्ताक्षर कर किया फर्जीवाड़ा

राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर की गड़बड़ियां तो सामने आती रहती हैं, लेकिन संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीटी और एमआरआई करने वाली कंपनी ने ही मरीजों के फर्जी दस्तावेजों और डॉक्टरों के फर्जी साइन और सील लगाकर करोड़ों रुपए का क्लेम उठा लिया।

चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने आरोपी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आश्चर्य की बात है कि जिस कंपनी पर खुद चिकित्सा विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई और उसे डिपेनल करने के बाद भी जोधपुर और बीकानेर मेडिकल कॉलेज में करीब 20 करोड़ रुपए के टेंडर भी दे दिए। जांच के दौरान कई ओपीडी स्लिप में डॉक्टरों के साइन ही नहीं है। वर्ष 2024-25 के बीच की गई इस गड़बड़ी में ओपीडी पर्चियों पर जिन डॉक्टरों के साइन है वे वास्तव में वहां डॉक्टर ही नहीं थे। मामले की अभी भी जांच चल रही है। *(दै.भा., 07.06.26)*

## बाजार में बेच दिया बच्चों का निवाला

सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील के गेहूं व चावल की सप्लाई में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सामान सप्लाई करने वाली फर्म ने ही 2426 क्विंटल गेहूं व चावल बाजार में बेच खाया। अब रसद विभाग व शिक्षा विभाग ने फर्म प्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया है।

सीकर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मिड डे मील में फूड प्रोडक्ट सप्लाई के लिए अगस्त 2024 से मार्च 2025 के लिए बिलाड़ा की मैसर्स भवानी इंडस्ट्रीज का टेंडर एक साल के लिए दिया गया था। इसी फर्म की ओर से फर्जीवाड़ा किया गया है। जांच में सामने आया है कि फर्म को जुलाई 2024 से सितंबर 2025 तक स्कूलों में देने के लिए कुल 20233 क्विंटल गेहूं व 10586.6 क्विंटल चावल दिए गए थे। इसमें से 1622. 624 किलो गेहूं और 826.84 किलो चावल स्कूलों में दिया ही नहीं गया। *(दै.भा., 04.06.26)*

### तय बजट का 77 फीसदी ही खर्च

दुनिया में जियो-पॉलिटिकल उथल-पुथल के बीच अर्थव्यवस्था मजबूत करने व रोजगार सृजन के लिए केंद्र सरकार बुनियादी ढांचा विकास के पूंजीगत खर्च पर जोर दे रही है, लेकिन राज्यों के लचर प्रशासन उसकी योजना से कदमताल नहीं कर पा रहे।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ओर से राज्य के जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 20 राज्यों में पूंजीगत व्यय के लिए 10.26 लाख करोड़ रुपए तय किया गया था लेकिन मार्च 2026 में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक असमें से केवल 10.26 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। खर्च के मामले में तेलंगाना और कर्नाटक अव्वल रहे जबकि भाजपा शासित राजस्थान व छत्तीसगढ़ जैसे राज्य सबसे फिसड्डी साबित हुए। सीएजी के ताजा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान सरकार तय पूंजीगत बजट का 51फीसदी ही खर्च कर पाई। *(रा.प., 19.05.26)*

### बेकार पड़े करोड़ों के मेडिकल उपकरण

सरकारी अस्पतालों में एक ओर मरीज संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों रुपए के आधुनिक मेडिकल उपकरण वर्षों से बेकार पड़े हैं। राज्य सरकार की जांच में सामने आया है कि 25 करोड़ रुपए के 1824 उपकरण, जिनमें 159 से अधिक वेंटिलेटर शामिल है, विभिन्न अस्पतालों में उपयोग में नहीं आ रहे।

तैयार सूची में 653 इन्फ्यूजन पंप, 212 रेडिएंट हीट वार्मर, 159 वेंटिलेटर, 142 बाइपेप मशीन और 132 फोटोथेरेपी यूनिट शामिल है। कुछ जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर, मॉनिटर और एक्सरे मशीन जैसे महंगे उपकरण बिना उपयोग के पड़े हैं। स्थिति यह है कि कई अस्पतालों में उपकरण होने के बावजूद मरीज को जांच और इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है।

*(रा.प., 30.04.26)*

### खाद बीज कारोबार में बड़ा छेद

राज्य में नकली और अमानक खाद-बीज के कारोबार की जड़ें कितनी गहरी है, इसका खुलासा पिछले 26 माह में हुई कार्रवाई से हुआ है। कृषि विभाग ने 89 खाद-बीज और कीटनाशक निर्माण इकाइयों में अनियमितता पकड़ते हुए 41 मामलों में जब्ती की कार्रवाई की, जबकि कई फर्मों के लाइसेंस रद्द और निलंबित किए गए।

जनवरी 2024 से मार्च 2026 के बीच कृषि विभाग की ओर से हुए निरीक्षण में संदिग्ध पाए गए खाद-बीज के 41 मामलों में जब्ती की कार्रवाई की गई, जबकि कई फर्मों के लाइसेंस रद्द या निलंबित कर दिए गए। *(रा.प., 11.06.26)*

### ऐसे तो हालत नहीं बदलेंगे..सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मौजुदा आरक्षण व्यवस्था पर बुनियादी सवाल उठाते हुए अहम टिप्पणी की है। ओबीसी क्रीमिलेयर आरक्षण संबंधी एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यदि माता-पिता भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारी हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बैंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ (डीबी) के फैसले के खिलाफ अपील के दौरान यह टिप्पणी की। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि आप कमजोर वर्ग को आरक्षण दे रहे हैं। माता-पिता ने पढ़ाई की है, वे अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छी आमदनी है और बच्चे फिर से आरक्षण चाहते हैं। फिर आरक्षण का क्या फायदा? ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर निकलना चाहिए। *(रा.प., 23.05.26)*

### इलाज 25 से 96 फीसदी हुआ महंगा

प्रदेश में प्रमुख बीमारियों के इलाज का औसत खर्च 8 साल में 25% से 96% तक महंगा हो गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के मुताबिक, श्वसन बीमारियों का खर्च प्राइवेट अस्पतालों में 96.4% बढ़कर 47,240 रुपए पहुंच गया है। जबकि पाचन तंत्र की बीमारियों का इलाज 76.3% तक महंगा हुआ है।

सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में दिल के इलाज का खर्च 50% से ज्यादा बढ़ा है। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्च सरकारी के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर आंखों के इलाज का खर्च सरकारी अस्पताल में करीब 2,500 रुपए है, जबकि शहरी प्राइवेट अस्पतालों में 33,276 और ग्रामीण में 22,156 रुपए तक पहुंच जाता है। चिकित्सा तकनीक और दवाओं की बढ़ती कीमत से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा हुआ है। आम मरीजों के लिए यह बड़ा आर्थिक बोझ बन रहा है। *(दै.भा., 04.05.26)*

### कर्ज में डूब रहे हैं हम...?

राजस्थान सरकार का सार्वजनिक ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 तक राज्य पर कुल बकाया कर्ज बढ़कर 5,65,814.94 करोड़ हो गया, जो 31 मार्च 2024 में को 4,46,651.63 करोड़ था। यानी महज दो साल में करीब 1.19 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई।

यह जानकारी 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र में विधायक यूनुस खान की ओर से पूछे गए तारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में सामने आई। राज्य सरकार कर्ज के ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है, जहां पुराने कर्ज की अदायगी के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ रहा है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है।

*(दै.भा., 24.05.26)*

### डिजीटल हेल्थ मिशन की जमीनी हकीकत

प्रदेश में डिजीटल हेल्थ मिशन की रफ्तार कागजों में तो तेज दिख रही है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। अभी भी करीब 60 फीसदी मरीज आभा आइडी से दूर है। आभा आइडी में मरीज का पूरा रिकॉर्ड एक जगह होता है। बार-बार रजिस्ट्रेशन से राहत मिलती है। किसी भी अस्पताल में इलाज का डेटा साझा हो सकता है।

ग्रामीण और छोटे शहरों में लोग आइडी तो बनवा लेते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते। डिजिटल हेल्थ मिशन की बड़ी चुनौती तकनीकी और व्यावहारिक है। ओटीपी आधारित लॉग-इन प्रक्रिया कई मरीजों के लिए जटिल है और इससे उनको निजता का डर बना रहता है।

*(रा.प., 10.05.26)*

# सतत् विकास लक्ष्यों की योजना

*हम दुनिया का कायाकल्प करने की दहलीज पर खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत् विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक सम्पन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जाएगा।*

*गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि और उत्कृष्ट कार्य, बुनियादी सुविधाएं, उद्योग एवं नवाचार, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर, उपभोग व उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक प्रणालियां, शांति एवं न्याय और भागीदारी।*

## जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ा

विश्व पर्यावरण दिवस पर यूनीसेफ और फ्यूचर सोसायटी की ओर से मीडिया कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन से राजस्थान में बढ़ते संकट पर चिंता जताई। यूनीसेफ के चीफ के.एल.राव ने कहा कि हीटवेव और जल संकट का सर्वाधिक असर बच्चों व महिलाओं पर पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि जागरूकता में मीडिया की भूमिका अहम है। शिक्षा विभाग के साथ हीटवेव शिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख राधेश्याम शर्मा ने कहा कि अनियमित वर्षा व भूजल दोहन से जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। यूनीसेफ के अंकुश सिंह ने 'यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन' पहल की जानकारी दी। डॉ. मीना शर्मा ने जलवायु स्मार्ट स्कूलों व युवा भागीदारी पर जोर दिया। *(रा.प., 05.06.26)*

## लागू होगा वीबी-जी-राम-जी

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून (वीबी-जी-राम-जी) अगले महीने यानी 1 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही मनरेगा खत्म हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है।

सरकार के अनुसार 30 जून तक मनरेगा के तहत चल रहे काम नए ढांचे में शामिल होंगे। ई-केवाईसी से सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड नए 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' जारी होने तक मान्य रहेंगे। ई-केवाईसी लंबित होने पर रोजगार नहीं रुकेगा। *(दै.भा., 12.05.26)*

## प्रदेश में बदलता मानसून का स्वरूप

प्रदेश में जहां एक ओर हरियाली और बारिश बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर मौसम का असंतुलन नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है। प्रदेश में बारिश का पैटर्न बदलता जा रहा है। जहां पहले पूर्वी हिस्सों में ज्यादा बारिश होती थी वहीं अब पश्चिमी जिलों में वृद्धि अधिक दर्ज हो रही है।

पिछले एक दशक से जलवायु परिवर्तन ने पश्चिमी राजस्थान की पारिस्थितिकी को पूरी तरह प्रभावित किया है। जहां रेत थी वहां हरियाली नजर आने लगी है। कृषि क्षेत्र में भी 74 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है। इस बदलाव ने ईकोसिस्टम को नया रूप दिया है। हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बढ़ता तापमान, भूजल दोहन व शहरीकरण इस संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसलिए भूजल संरक्षण को खास महत्व दिया जाए। *(रा.प., 22.04.26)*

## वन क्षेत्र बढ़ाने में भारत तीसरे स्थान पर

भारत वन क्षेत्र बढ़ाने में चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में दसवें से नौवें स्थान पर पहुंच गए है। भारत पांचवा सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। हमारे जंगल हर साल 15 करोड़ टन कार्बन सोख रहे हैं।

सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले 17 देशों में भारत शामिल है। 1445 वर्ग किमी हरित क्षेत्र देश में 2 साल में बढ़ा है। यह लगभग एक बड़े क्षेत्रफल के बराबर है। *(दै.भा., 22.06.26)*

## औद्योगिक निवेश का बना नया केंद्र

केंद्र सरकार की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान ने औद्योगिक निवेश के मामले में देश में 8वें स्थान से तीसरे स्थान पर जगह बना ली है। महाराष्ट्र, गुजरात और एनसीआर से बेहतर कनेक्टिविटी के चलते जयपुर तेजी से एक मजबूत इन्वेस्टमेंट हब के रूप में विकसित हो रहा है।

प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर गंभीरता से काम हो रहा है। वेयरहाउस व फैक्ट्री स्पेस का राज्य नया केंद्र बना है। एक साल में ही करीब 5,000 करोड़ के सौदे हो चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जल्द ही कुछ और बिजनेस ग्रुप जयपुर के आसपास बड़ा निवेश करने वाले हैं। *(रा.प., 05.05.26)*

## भारत में चाहिए 'तिलहन क्रांति'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने की अपील की है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत पेट्रोल-डीजल के बाद सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा खाद्य तेल खरीदने में करता है।

भारत करीब 60 प्रतिशत खाद्य तेल विदेशों से मंगाता है, जिस पर करीब 18.3 लाख डॉलर यानी 1.61 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। विशेषज्ञों का मानना है हरित क्रांति की तर्ज पर अब तिलहन क्रांति की जरूरत है। ताकि देश खाद्य तेल के मामले में भी आत्मनिर्भर हो सके। राज्य अभी अपनी जरूरत से लगभग दोगुना तेल पैदा कर रहा है। *(रा.प., 13.05.26)*

## प्रदेश में लगाए जाएंगे 10 करोड़ पौधे

राज्य सरकार इस बार भी मानसून के दौरान दस करोड़ पौधे लगाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश को 'हरियालो राजस्थान' बनाया जाए। इसके लिए पांच साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई वन एवं पर्यावरण विभाग की बैठक में पौधारोपण लक्ष्य, चंदन वन, नमो वन एवं नमो नर्सरी की स्थापना के बारे में निर्णय लिए गए। पौधारोपण अभियान की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव को अधिकृत किया गया है। पौधारोपण कार्य विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) से प्रारंभ कर दिया जाएगा। अभियान के तहत किसानों को भी मुफ्त फलदार पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे।
*(रा.प., 05.04.26)*

## भ्रष्ट व लापरवाह अफसरों पर एक्शन

भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, अनियमितता और लापरवाही जैसे मामलों को लेकर सरकार ने ढाई साल में कई अधिकारियों पर कार्रवाई की है। एक आरएएस सहित 20 अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया है। 332 अधिकारियों और कार्मिकों को निलंबित किया है, जबकि 17 की पेंशन रोकी है। 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी की है और 577 प्रकरणों में जांच कर जिम्मेदारी तय की जा रही है।

राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार और लापरवाही में सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फाइलों को लंबित रखना, सरकारी धन का दुरुपयोग और जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति स्वीकार नहीं होगी। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सख्त संदेश है कि सरकारी सेवा जन सेवा के लिए है और जिम्मेदारी में लापवाही और अनियमितता पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। *(दै.भा., 01.06.26)*

## घपलों पर एआई डैशबोर्ड रखेगा निगरानी

राजस्थान में वित्तीय प्रबंधन में बड़ा बदलाव होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में महालेखा नियंत्रक के साथ वित्तीय प्रबंधन पर हुए मंथन के बाद तय हुआ कि राजस्थान में संचालित केंद्र की 70 और प्रदेश की 160 योजनाओं यानी 230 योजनाओं के वित्तीय घपलों और ट्रांजेक्शन की निगरानी के लिए एआई डैसबोर्ड तैयार किया जाएगा।

मुख्यसचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की महालेखा नियंत्रक टीसीए कल्याणी ने पीएफएमएस-आईएफएमएस सहित विभन्न वित्तीय प्रबंधन विषयों पर विस्तृत चर्चा की। कल्याणी ने बताया कि प्रदेश में समायोजित प्रणाली एकीकरण शीघ्र हस्तांतरण वर्तमान में 70 केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा 160 राज्य स्तरीय योजनाएं शामिल की जा चुकी है। वित्तीय निगरानी एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब एआई डैशबोर्ड से रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। *(दै.भा., 13.05.26)*

## रंगे हाथों पकड़ा तो बजाए ढोल

प्रदेश के पाली जिले की बाली तहसील के लाटाड़ा गांव में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पटवारी विक्रम धीर को 8 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और ढोल बजा कर खुशी जताई।

ग्रामीणों के अनुसार पटवारी बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं करता था। एसीबी के अनुसार पटवारी ने परिवादी की क्रय की गई भूमि के नामांतरण और विभाजन के लिए 11 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी। पहले वह 5 हजार रुपए ले चुका था। इसके अलावा वह परिवादी की मां के नाम दर्ज भूमि के सीमांकन के लिए 2 हजार रुपए और पहले किए कार्यों की एवज में 6 हजार रुपए और मांग रहा था। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन के बाद जाल बिछाया और पटवारी विक्रम धीर को 8 हजार रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। यह खबर प्रदेश के गांवों के लिए प्रेरणा दायक है।

*(रा.प., 02.06.26)*

### भ्रष्टाचार की बानगियां

| जिला | रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम | कार्यरत विभाग का नाम व पद | रिश्वत में ली राशि (रुपए में) | स्त्रोत |
|---|---|---|---|---|
| करौली | काजल मीणा<br>दिनेश सैनी<br>प्रवीण धाकड़ | नादौती एसडीएम (आरएएस अधिकारी) करौली<br>रीडर<br>यूडीसी | 60,000 | *रा.प. एवं दै.भा., 17.04.26* |
| दौसा | आदित्य शर्मा | लैब असिस्टैंट, उपखंड अधिकारी कार्यालय, बांदीकुई | 15,000 | *रा.प., 21.04.26* |
| भीलवाड़ा | शहजाद<br>मोड़ूराम<br>बनवारी | एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी, भीलवाड़ा<br>ठेकेदार<br>ठेकेदार | 4,00,000 | *दै.भा., 06.05.26* |
| उदयपुर | शेखर मथूरिया | वरिष्ठ सहायक, जीपीएफ | 1,00,000 | *रा.प., 13.05.26* |
| झुंझुनूं | राजकुमार | ग्राम विकास अधिकारी, बेरला ग्राम पंचायत | 8,50,000 | *दै.भा., 26.05.26* |
| श्रीगंगानगर | रामेश्वरलाल विश्नोई | एसआई, घड़साना पुलिस थाना | 20,000 | *दै.भा., 26.05.26* |
| धौलपुर | रमेश कुमार | कनिष्ठ सहायक, बसेड़ी पंचायत समिति, ग्रा.प.रतनपुर | 25,000 | *रा.प., 04.06.26* |
| टोंक | नवनीत सिंह गुर्जर<br>मोहम्मद शाजिम | सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम,टोंक<br>कम्प्यूटर आपरेटर, जयपुर विद्युत वितरण निगम,टोंक | 20,000 | *रा.प., 06.06.26* |
| कोटपूतली | प्रमोद सामरिया | पटवारी, भैंसलाना हल्का | 40,000 | *दै.भा., 07.06.26* |
| बूंदी | मुकेश कुमार | ग्राम विकास अधिकारी, गरड़दा पंचायत | 50,000 | *दै.भा., 16.06.26* |
| जयपुर | संजयकुमार बैरवाक | निष्ठ अभियंता, नगर निगम जयपुर | 80,000 | *रा.प., 30.06.26* |

## विश्व में अनिश्चितता, भारत विकास पथ पर

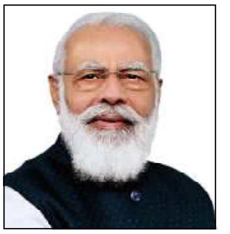

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग कांउसिल की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। इसके बावजूद भारत भरोसे और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे देश 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, देश की सामूहिक भागीदारी और बढ़ जाती है।

इस वर्ष बैठक की थीम 'विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास' रही। 28 राज्यों तथा 5 केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत में युवाओं के लिए सही इकोसिस्टम बनाना प्राथमिकता रहनी चाहिए। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मांग के अनुसार स्किलिंग, रोजगार के अवसर शामिल है। इससे सशक्त युवा 'विकसित भारत' की यात्रा की ताकत बनेंगे। *(रा.प., 12.06.26)*

### मिट्टी बचेगी तभी बचेगी खेती

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गांव रामसिया से राष्ट्रव्यापी स्तर पर 'खेत बचाओ अभियान' का शुभारंभ किया है। अभियान का खास मकसद किसानों को रासायनिक खेती से दूर कर केमिकल-मुक्त और जैविक खेती की ओर प्रेरित करना है।

उन्होंने कहा कि धरती की सेहत से खिलवाड़ रोकने के लिए हर खेत का सॉयल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। धरती की उर्वरा शक्ति को बचाने और खेती को टिकाऊ बनाने के लिए केंद्र सरकार इस अभियान के तहत स्वस्थ मिट्टी के जरिए किसानों को सशक्त बना रही है। मिट्टी बचेगी तभी खेती बचेगी, किसान मजबूत होगा और देश समृद्ध बनेगा। एक विशेष मोबाइल ऐप की मदद से मिट्टी की जांच कर यह पता लगाया जा रहा है कि जमीन को कितने खाद की आवश्यकता है। *(रा.प., 02.06.26)*

### प्रदेश के कृषि बाजार की बढ़ेगी ताकत

प्रदेश में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026 के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग उद्योग, एग्रो-पार्क और कृषि क्षेत्र में निवेश के नए द्वार खुल रहे हैं। ग्राम 2026 की अहमदाबाद में हुई इन्वेस्टर मीट के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवेशकों को आमंत्रित किया, जिसमें डेयरी, फूड-पार्क, फूड प्रोसेसिंग व स्पाइस प्रोसेसिंग सेक्टर से संबंधित एमओयू हुए।

मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर मीट में कहा कि देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में आधुनिक, तकनीकी और लाभकारी बदलाव तेजी से हो रहे हैं। खेती में हो रही अलग-अलग फसलों की वजह से राजस्थान एग्री बिजनेस का पॉवरहाउस बनेगा। इससे प्रदेश में छोटे किसान कृषि बाजार की बड़ी ताकत बन सकेंगे। *(दै.भा., 01.05.26)*

### योजनाओं की जमीनी स्तर पर परख

प्रदेश में केंद्र व राज्य सरकार जमीनी स्तर पर एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत दी जा रही राहतों और सुविधाओं का वास्तविक रूप से कितना फायदा मिल रहा है, इसके लिए महालेखा परीक्षक (एजी) ऑडिट करेंगे और दी गई रियायतों, अनुमति और क्लीयरेंस प्रक्रिया तथा समयबद्ध सेवाओं के पालन की हकीकत का पता लगाएंगे।

इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर उद्योग विभाग और रीको के अधिकारियों के साथ एजी की बैठक भी हो चुकी है। इससे उद्योगों को मिल रही सुविधाओं की सच्चाई स्पष्ट होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, योजनाओं की कमियां सामने आएंगी, प्रशासकीय प्रक्रियाओं में सुधार होगा और निवेशकों का भरोसा बढ़ सकेगा।

*(रा.प., 14.04.26)*

### बाजरे की नई किस्म से बढ़ेगी पैदावार

केंद्र सरकार की 'श्री अन्न' (मिलेटस) को बढ़ावा देने की मुहिम के बीच जयपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने बाजरे की ऐसी हाइब्रिड किस्म विकसित की है, जो कम बारिश वाले क्षेत्रों में भी अधिक उत्पादन देने के साथ सूखे और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है।

जयपुर स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान (रारी) ने इक्रीसैट के सहयोग से देश की पहली थ्री-वे हाइब्रिड बाजरा किस्म 'आरएचबी-273' विकसित की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस वर्ष जारी 184 उन्नत फसल किस्मों में इसे शामिल किया है। इस किस्म को देश के ए जोन के लिए स्वीकृति मिली है। इससे राजस्थान के साथ हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के किसानों को लाभ मिलेगा।

*(रा.प., 31.05.26)*

### प्रदेश में पर्यटन को लगेंगे पंख

केंद्र सरकार के 'मेरा गांव मेरी धरोहर' प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के 40 हजार में से 25 हजार से ज्यादा गांवों का डिजिटल डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस पहल से न केवल ग्रामीण पर्यटन को पंख लगेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

डिजिटल प्रोफाइल में गांव की एतिहासिक विरासत, ग्रामीण पर्यटन, तीज-त्योहार, पारंपरिक शिल्प, खान-पान, पहनावा व गहने, धार्मिक मान्यताएं, गांव के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रमुख लोक कला जैसी बिंदुओं पर केंद्रित है। इससे अब विदेशी और घरेलू पर्यटक शहरों के साथ आस-पास के गांवों के दो-तीन दिन के भ्रमण की योजना भी बना सकेंगे ।

*(रा.प., 15.05.25)*

### आपणी बोली नूं मिल्यो मान

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि राजस्थानी भाषा को सभी सरकारी व निजी स्कूलों में एक विषय के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था कर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति व संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप राजस्थानी मातृभाषा के रूप में चरणबद्ध तरीके से पढ़ाई शुरू करने के लिए नीति बनाए।

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 26 सितंबर तक शपथ पत्र के साथ पालना रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद से प्रदेश के शिक्षा ढांचे में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है। विशेषज्ञों को मानना है, जब बच्चा अपनी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर से पढ़ाई करता है तो भाषा को सीखने की रुचि बढ़ जाती है। राजस्थानी एक मानक भाषा है जिसमें राज्य की सभी बोलियों का मिश्रण होता है।

*(रा.प., 13.05.26)*

## प्रदेश बनेगा ग्रीन एनर्जी नेटवर्क

राजस्थान के जैसलमेर जिले में करीब 1.50 लाख हेक्टेयर जमीन पर सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी नेटवर्क बनेगा। ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में सबसे बड़ा यह विदेशी निवेश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार कर रही है। प्रोजेक्ट के लिए अक्षय ऊर्जा निगम ने करीब 600 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी राशि मांगी है। राशि जमा होने के बाद जमीन आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

यूएई सरकार करीब 3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 60,000 मेगावाट क्षमता के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट विकसित करेगी, जिसके लिए मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नाम से रजिस्ट्रेशन पहले ही कराया जा चुका है। इन प्रोजेक्ट में सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज और बायोमास आधारित ऊर्जा परियोजनाएं शामिल होंगी। इसे देश में ग्रीन एनर्जी क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। *(रा.प., 17.05.26)*

## प्रदेश में बनी सबसे ज्यादा बिजली

राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नया रेकॉर्ड बनाया है। 7,580 मेगावाट क्षमता वाली 23 यूनिटों से 7,171 मेगावाट बिजली उत्पादन किया। यह निगम के गठन के बाद से अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। इस दौरान स्थापित क्षमता का 94.60 प्रतिशत उपयोग हुआ।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। प्रदेश में अब 26 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली सिंचाई के लिए बिजली मिलने लगी है। प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ने से बाजार से बिजली खरीदने की जरूरत काफी कम हो गई है। पिछले साल मई में राज्य को अपनी कुल जरूरत का करीब 8 प्रतिशत बिजली बाजार से खरीदनी पड़ी थी, जो अब घटकर 2 प्रतिशत पर आ गई है।

*(रा.प., 04.06.26).*

## चोरी व मीटर से छेड़छाड़ पड़ेगी भारी

प्रदेश में बिजली चोरी और मीटर से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार द्वारा बिजली अधिनियम 2003 में किए गए संशोधन के बाद 1 जून से नए दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे। नए नियमों के तहत बिजली चोरी, अवैध कनेक्शन, मीटर में गड़बड़ी व विद्युत संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर आर्थिक दंड वसूला जाएगा।

बिजली विभाग की संपत्ति जैसे ट्रांसफार्मर, बिजली लाइन, खंभे, मीटर सा अन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचाने पर 5 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। नियमों या विभागीय आदेशों की अवहेलना करने पर 10 हजार से लेकर 5 लाख रुपए तक की पैनल्टी लगाई जा सकती है। उल्लंघन जारी रखने पर अतिरिक्त जुर्माना भी वसूला जाएगा। डिस्कॉम का मानना है कि बिजली चोरी से हर साल डिस्कॉम को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, जिसका भार अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

*(दै.भा., 31.05.26)*

## प्रदेश में नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें

प्रदेश के 1.75 करोड़ से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं के लिए यह राहत की खबर है कि इस वर्ष सभी श्रेणियों में बिजली की दरें यथावत रखी गई है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर फिक्स जार्च समाप्त कर दिया गया है। अब इन कनेक्शनों पर 150 रुपए प्रति केवीए तक चार्ज नहीं लगेगा, जिससे चार्जिंग सस्ती होगी। मध्यम श्रेणी के उद्योगों को 30 पैसे यूनिट की राहत दी गई है। अब न्यूनतम विद्युत शुल्क 6.30 प्रति यूनिट से घटाकर 6 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है। इससे उन्हें विभिन्न छूटों का अधिक लाभ मिलेगा। *(रा.प., 03.04.26)*

## ऊर्जा बचत को मिलेगा कानूनी आधार

प्रदेश में भवन निर्माण को ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही राजस्थान एनर्जी कंजरवेंयन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड-2026 लागू करने जा रही है।

इसके तहत बड़े व्यावसायिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और कार्बन उत्सर्जन में कमी के न्यूनतम मानक तय किए जाएंगे। खास बात यह है कि इनका पालन करने वाले भवनों को पहली बार अतिरिक्त बिल्ट एरिया रेश्यो का प्रोत्साहन मिलेगा।

*(रा.प., 21.06.26)*

## 'एनर्जी सरप्लस स्टेट' बनेगा प्रदेश

राजस्थान अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की कुसुम-2.0 योजना के तहत प्रदेश को 6,000 मेगावाट सोलर पावर क्षमता आवंटित की गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से प्रदेश की पीक डिमांड को पूरा करना है।

ऊर्जामंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि प्रदेश में अब 6 हजार मेगावाट बैटरी स्टोरेज से तस्वीर बदली है। इससे प्रदेश एनर्जी सरप्लस स्टेट बनेगा। *(दै.भा., 05.06.26)*

## प्रसारण में विद्युत क्षति जनता पर भारी

राजस्थान में विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार के बावजूद ट्रांसमिशन लॉसेज (प्रसारण क्षति) अधिक होने से उपभोक्ताओं पर हर साल 2348 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। राजस्थान में प्रसारण क्षति कई राज्यों से अधिक है वहीं ग्रिड प्रबंधन में भी प्रदेश पड़ोसी राज्यों से पिछड़ा है।

राजस्थान में विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज (वितरण क्षति) में कमी आई है, लेकिन प्रसारण स्तर पर अधिक क्षति होने के कारण वितरण निगमों को अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ रही है। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ के रूप में पड़ रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक राज्य के अन्दर प्रसारण क्षति को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4.25%, 2025-26 में 4.20% और 2026-27 में 4.05% स्वीकृत किया है। राज्य में प्रसारण तंत्र वास्तविक मांग के अनुरूप विकसित करने की जरूरत है।

*(रा.प., 11.04.26)*

## मानसून से पहले बांधों की 'हेल्थ चेक'

केंद्र सरकार डेम सेफ्टी एक्ट के तहत देशभर के 6000 से भी अधिक बांधों की पहली बार संयुक्त जांच करवा रही है। इसका उदेश्य बांधों की स्थिति, सुरक्षा और रखरखाव की जानकारी जुटाना है। इसके आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी, जिससे बदहाल स्थिति वाले बांधों की पहचान हो सके।

राजस्थान में डेम सेफ्टी एक्ट के तहत प्रदेश में छोटे बड़े 315 बांधों की सेहत जांचने का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि मानसून से पहले किसी भी खतरे या कमी को समय रहते दूर किया जा सके। जांच के दौरान बांधों की मजबूती, रखरखाव, मरम्मत, जलभराव क्षमता और सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन किया जा रहा है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि बांधों के जल भराव क्षेत्रों में अतिक्रमण तो नहीं बढ़ गए हैं, जिससे पानी की आवक प्रभावित हो रही हो। *(रा.प., 20.05.26)*

## पाताल में पानी, शहरों में स्थिति विकट

भारत के बड़े शहरों में भू-जल का स्तर खतरनाक गति से गिर रहा है। आइआइटी रुडकी के शोधकर्ताओं ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के 54 प्रमुख शहरों पर किए गए अध्ययन में इस गंभीर खतरे के प्रति आगाह किया है। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कई इलाकों में भी भू-जल तेज गति से नीचे जा रहा है।

मसलन, जयपुर में भूजल दोहन की दर 341% तक पहुंच चुकी है। झोटवाड़ा, मुरलीपुरा और जगतपुरा जैसे इलाकों में भूजल लगभग समाप्त हो रहा है। जबकि पानी की मांग हर साल 10% बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, सहारनपुर, बडोदरा और मुंबई बेहद जोखिमपूर्ण माने गए हैं। रिपोर्ट में भू-जल गिरावट की मुख्य वजह भू-जल का अत्यधिक दोहन, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन बताई गई है। *(रा.प., 06.04.26)*

## नल से जल की रफ्तार काफी धीमी

देशभर में ग्रामीण घरों तक नल से पेयजल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना ने कई राज्यों की तस्वीर बदल दी है। वहीं जल संकट और सूखे की चुनौती झेलने वाला राजस्थान अभी राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के 1.07 करोड़ परिवारों में से केवल केवल 63.48 लाख घरों तक ही नल से जल आपूर्ति पहुंच पाई है। अर्थात राज्य की कवरेज मात्र 63.48 लाख घरों तक ही है। अभी भी करीब 44 लाख परिवार घर-घर नल-जल सुविधा से वंचित हैं। यह स्थिति तब है जब राज्य में जल जीवन मिशन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हालांकि अब राजस्थान में लगातार कनेक्शनों को लेकर रफ्तार बढ़ रही है। एक ही दिन में 1500 से ज्यादा कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, जब कि अन्य राज्यों में यह आंकड़ा दो से तीन अंकों तक है। *(रा.प., 05.06.26)*

## गांवों के भूजल में हो रहा सुधार

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 से कम बारिश और गिरते भूजल स्तर से 5000 गांवों की तस्वीर बदली है। अभियान में वर्षा जल संचयन के लिए इन गांवों में एनीकट, चेक डैम, तालाब एवं जोहड़ बनाए गए हैं।

इससे पांच हजार गांवों के भूजल में सुधार हुआ है। कुओं व ट्यूबवेलों में जल स्तर बढ़ा है। गांवों में पेयजल व खेतों की सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बढ़ी है। बजट 2026-27 में इस अभियान के तीसरे चरण के तहत 2,500 करोड़ रुपए की लागत से 5000 गांवों में 1,10,000 कार्य करवाने की घोषणा की गई है। किए जा रहे कार्यों से प्रदेश जल संकट से उबरकर एक आदर्श मॉडल के रूप में सामने आएगा। *(दै.भा., 06.04.26)*

## 'जहरीला' पानी होगा रीसाइकिल

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण और भू-जल को जहरीला होने से बचाने के लिए नई कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) योजना लागू की गई है। इसके तहत रीको और गैर-रीको औद्योगिक क्षेत्रों में सीईटीपी का निर्माण होगा। इस पर 150 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।

खास यह है कि नए प्लॉट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक पर आधारित होंगे, जिससे ट्रीटेड पानी का दोबारा उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही पुरानी सीईटीपी योजना का दायरा बढ़ाकर अनुदान सीमा 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रीको और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक मंडल वित्तीय सहायता देंगे। वहीं गैर-रीको औद्योगिक क्षेत्रों में सहायता राज्य सरकार और राजस्थान प्रदूषण मंडल स्तर पर दी जाएगी। *(रा.प., 27.05.26)*

## डूंगरपुर बना जल प्रबंधन की मिसाल

प्रदेश का डूंगरपुर जिला अब जल प्रबंधन की मिसाल बनकर उभर रहा है। यहां पिछले पांच सालों में 7 हजार 535 चेकडेम बनाए गए हैं। इन संरचनाओं से जिले में औसतन 6.5 मीटर तक भूजल स्तर बढ़ा है।

गांवों में जहां पहले गर्मियों में गंभीर जल संकट होता था, वहां अब जल स्रोत लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। इन गांवों में पानी की उपलब्धता पहले के मुकाबले दोगुनी हो गई है। जिले में जो कुएं और हैंडपंप पहले सूख जाते थे, वे अब लगातार पानी उपलब्ध कराते हैं। 15 साल से बंद पड़े कुंए फिर से उपयोग में आने लगे हैं। सिंचाई सुविधाएं मजबूत होने से इसका किसानों को भी बड़ा फायदा मिला है। *(दै.भा., 07.04.26)*

## बुझेगी प्रदेश के वागड़ अंचल की प्यास

जल संसाधन विभाग का अपर हाई लेवल केनाल प्रोजेक्ट वागड़ अंचल के जनजाति बहुल इलाकों की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएगी। प्रोजेक्ट में 102 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर का निर्माण किया जा रहा है।

करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से बांसवाड़ा जिले के 338 गांवों की 42 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। परियोजना से बांसवाड़ा, बागीदौरा और कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के 3.5 लाख लोगों को फायदा होगा। *(दै.भा., 08.06.26)*

## महिलाएं संभालेंगी मार्केट तक कमान

प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार अब डेयरी सहकारिता और स्वयं सहायता समूहों को एक मंच पर लाने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजीविका और आरसीडीएफ (सरस) मिलकर एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करेंगे, जिससे ग्रामीण और शहरी महिलाओं को डेयरी आधारित रोजगार से सीधा जोड़ा जाएगा।

सरस की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि राजीविका द्वारा संचालित 273 लखपति दीदी कैंटीनों पर अब सरस ब्रांड का दूध और दूध से बने सभी तरह के उत्पाद उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पहले चरण में प्रदेश के सभी जिला कलेक्ट्रेट परिसरों में सरस कैंटीनों में सरस बूथों के संचालन में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। *(दै.भा., 08.05.26)*

## पारित नहीं हुआ महिला आरक्षण बिल

महिलाओं को लोकसभा व विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण का कानूनी कागजी हक 2023 में मिला, लेकिन इसे 2029 के आम चुनाव में लागू करने के लिए लाया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक फिलहाल लोकसभा में पारित नहीं हो पाया।

विधेयक को पारित करने के लिए दो-तिहाई यानी 352 वोट आवश्यक थे। लेकिन पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। अर्थात विधेयक को पारित करने के लिए 54 वोट कम पड़ गए। इससे फिलहाल महिला आरक्षण बिल फिर अटक गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि वह 2029 से महिला आरक्षण लागू करने के प्रयास जारी रखेंगे। *(रा.प., 18.04.26)*

## ई-श्रम पोर्टल पर नारी शक्ति

देश में असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में ई-श्रम पोर्टल पर हुए नए पंजीकरणों में महिलाओं की हिस्सेदारी 68.78 रही, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा में यह हिस्सा 68.05 प्रतिशत दर्ज किया गया।

यह रुझान दर्शाता है कि बड़ी संख्या में महिलाएं असंगठित कार्यबल में शामिल हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और अवैतनिक पारिवारिक कार्य में बढ़ती भागीदारी के कारण है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 2023 की रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि करती है कि वैश्विक स्तर पर कृषि, घरेलू कार्य और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में अनौपचारिक रोजगार में महिलाओं की संख्या अधिक है। *(दै.भा., 23.06.26)*

## श्रमिक बेटियों के लिए 'शुभ शक्ति'

राजस्थान श्रम विभाग की शुभ शक्ति योजना के तहत निर्माण श्रमिक परिवार की अविवाहित बेटियों/महिलाओं को 55,000 रुपए की सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिक परिवार की बेटियों को शिक्षा और स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त बनाना है।

स्वीकृत राशि का उपयोग शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार या विवाह में किया जा सकता है। इस योजना में पात्रता के लिए बेटियों की 18 वर्ष की आयु, 8वीं कक्षा पास और श्रमिक का एक वर्ष का पंजीकरण आवश्यक है। आवेदन ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों माध्यम से किए जा सकते हैं। *(दै.भा., 13. 04.26)*

## महिलाओं की निवेश में बढ़ी हिस्सेदारी

भारतीय बाजार में अब महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। महिलाए सोना, चांदी एफडी जैसे पारंपरिक निवेश से बाहर निकल कर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में भी पैसा निवेश कर रही है। खास यह है कि कुल 41.50 करोड़ निवेशकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 32% ही है। फिर भी वे कुल व्यक्तिगत एयूएम का 37% और कुल ग्रॉस इनफ्लो का 35% योगदान दे रही है। यानी प्रति निवेशक औसत निवेश क्षमता के मामले में पुरुषों से आगे है।

गौरतलब यह भी है कि टॉप 30 शहरों में 55% महिला निवेशक हैं, लेकिन इसके आगे के टॉप 30 यानी छोटे शहरों और कस्बों से 45% महिलाएं निवेश कर रही है। यह ही नहीं महिलाएं जोखिम से भी लड़ने में भी सक्षम बन रही हैं। *(दै.भा., 20.05.26)*

## होममेकर नहीं, राष्ट्र निर्माता हैं गृहणियां

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि घर संभालने वाली महिलाएं सिर्फ होममेकर नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता हैं। वाहन दुर्घटना मुआवजे से जुड़े केस में कोर्ट ने कहा कि महिला की मृत्यु 'घरेलू देखभाल का नुकसान' है।

मुआवजे की गणना के लिए महिला के घरेलू श्रम का मूल्य कम से कम 30 हजार रुपए प्रति माह माना जाए। कोर्ट ने कहा कि यह राशि हर तीसरे साल 10 प्रतिशत बढ़ेगी। कोर्ट ने कहा महिलाओं के घरेलू काम का जीडीपी में 15% से 17% योगदान माना जाता है। महिलाएं रोज 7 घंटे से अधिक अवैतनिक कार्य करती हैं। महिलाओं की मानव पूंजी निर्माण में बड़ी भूमिका है। जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और देश के सपने टिके हैं। *(दै.भा., 12.06.26)*

## महिलाएं बन रही आर्थिक वृद्धि की नई पहचान

राजस्थान की ग्रामीण महिलाएं अब केवल घर और खेत तक सीमित नहीं रही हैं, बल्कि प्रदेश की आर्थिक वृद्धि की नई पहचान बन रही है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की श्रम में भागीदारी शहरी महिलाओं की तुलना में लगभग दोगुनी है।

मनरेगा जैसी योजनाओं के अलावा खेतों में फसल उत्पादन, पशुपालन, दुग्ध समितियों के संचालन, स्वयं सहायता समूहों में प्रबंधन, ड्रोन दीदी और बैंक सखी जैसी कई भूमिकाओं तक, ग्रामीण महिलाएं आर्थिक गतिविधि के केंद्र में हैं। सर्वे मे सामने आया कि शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी का मुख्य कारण है कि वे ज्यादातर कौशल आधारित कार्यों से जुड़ी है, जो सीधे उनकी आजीविका का साधन बनते हैं। ग्रामीण महिलाओं का 88 प्रतिशत स्वरोजगार में होना यह साबित करता है कि उनके श्रम के बल पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है। *(रा.प., 21.06.26)*

## फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सुरक्षित फुटपाथ पर चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता । जस्टिस ए.एस. चंदूरकर की पीठ ने कहा यदि कोई सड़क है तो उसके साथ पैदल चलने वालों के लिए अलग और सुरक्षित फुटपाथ का निर्माण और रखरखाव करना संबंधित अधिकारियों का कानूनी दायित्व है। मोटर वाहनों को सड़क का विशेषाधिकार प्राप्त हो सकता है लेकिन यह पैदल चलने वालों के मौलिक अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी नागरिक के सुरक्षित रूप से पैदल चलने के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह संबंधित अधिकारियों के खिलाफ संवैधानिक और दीवानी उपायों का सहारा ले सकता है। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने का अधिकार भी बना रहेगा। अदालत ने कहा पैदल चलने वालों के अधिकारों को लेकर कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं है। इसलिए उनके अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए एक नियामक संस्था के गठन की जरूरत है। *(रा.प. एवं दै.भा., 20.06.26)*

## खुली फर्जी ड्राइविंग स्कूलों की पोल

राजधानी जयपुर में भारी वाहन चालकों को बिना किसी प्रशिक्षण के लाइसेंस थमाए जा रहे हैं। आरटीओ प्रथम जयपुर की ओर से किए गए 'डिकॉय ऑपरेशन' ने शहर के मोटर ड्राइविंग स्कूलों की पोल खोल दी है। बिना एक दिन भी गाड़ी चलवाए 500 से अधिक अनुभव प्रमाणपत्र जारी कर, इन्हीं प्रमाणपत्रों के आधार पर लाइसेंस भी दे दिए गए।

इस खुलासे में परिवहन व्यवस्था की खामियों ने आरटीओ प्रथम के कुछ अधिकारियों और कार्मिकों की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। लगातार शिकायतें मिलने के बाद आरटीओ प्रथम ने अपने स्तर पर जांच कराई तो अधिकारियों की करतूतें सामने आ गई। पता चला कि शहर के अधिकतर व्यावसायिक मोटर ड्राइविंग स्कूलों का अस्तित्व केवल कागजों तक ही सीमित है। वहां न तो ट्रक मौजूद है न ही प्रशिक्षण का कोई तंत्र। *(रा.प., 05.05.26)*

## रात को सड़कें हो जाती हैं खतरनाक

सावधान रहें, दिनभर की भीड़भाड़ के बाद रात को 9 बजे के बाद देश की सड़कें खतरनाक हो जाती हैं। रात को सड़कें खाली मिलते ही कई वाहन चालक तेज गति से वाहन चलाने लगते हैं। भारत में 80% से अधिक सड़क दुर्घटनाओं के पीछे मानवीय व्यवहार जिम्मेवार है।

इसका खुलासा एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी 'इंडिया रोड सेफ्टी रिपोर्ट 2026' में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार रात 9 से 10 बजे के बीच का समय भारत में सबसे जोखिम भरा घटा है, जबकि दोपहर 1 से 2 बजे बीच ड्राइविंग सबसे सुरक्षित पाई गई। रिपोर्ट 45 लाख से अधिक यात्राओं, 5.5 करोड़ किमी की ड्राइविंग और 27 हजार से ज्यादा चालकों के विश्लेषण पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार भारत हर साल करीब 1.73 लाख लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में खो देता हे।

*(रा.प., 26.06.26)*

## दुर्घटना के बाद मिले तत्काल सहायता

सुप्रीम कोर्ट ने दुर्घटना व ट्रॉमा में तत्काल इलाज के प्रति सख्ती बरतते हुए कहा है कि ट्रॉमा केयर उपलब्ध कराना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले नगरिकों को जीवन जीने के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।

जस्टिस जेके माहेश्वरी व जस्टिस एएस चंदुरकर की बैंच ने 'सेव लाइफ फाउंडेशन' की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तीन माह में आपातकालीन सेवाओं के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर की बजाय एकीकृत हेल्पलाइन नंबर '112' लागू करने और मददगार (गुड समैरिटन) शिकायत तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। बैंच ने आदेश की प्रति सभी राज्यों-यूटी के मुख्य सचिवों को भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्देशों की पालना पर रजिस्ट्री को रिपोर्ट पेश करे। गौरतलब है कि सड़क हादसों में शुरुआती'गोल्डन ऑवर' के दौरान समय पर इलाज मिलने से बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकती है। *(रा.प., 29.05.26)*

## सड़क हादसे रोकें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और तेलंगाना में लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के कड़े दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग 'मौत के कॉरिडोर' नहीं बनने चाहिए। प्रशासनिक लापरवाही व ढांचागत कमी के कारण लोगों की जान गंवाना राज्य की विफलता है।

राजस्थान में वर्ष 2022 में 11,104 मौतें दर्ज की गई जो 2025 में बढ़कर 12,069 हो गई थीं। प्रदेश में 40% मौतें नेशनल हाईवे और 25% मौतें स्टेट हाईवे पर होती हैं। सरकार हर साल सड़क सुरक्षा के लिए 100 करोड़ का फंड जारी करती है। देश में हो रहे हादसों से मौतों के मामले में राजस्थान 5वें नंबर पर है। उत्तरप्रदेश पहले, तमिलनाडु दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे और मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। जनवरी से मार्च 2026 के बीच राज्य में 6,436 हादसे हुए जिनमें 3,107 लोगों की मौत हो चुकी है। *(दै.भा., 20.04.26)*

## सुप्रीम कोर्ट सख्त, सिस्टम लापरवाह

राजस्थान में लगातार बढ़ते सड़क हादसे और उनमें जा रही लोगों की जानें भी परिवहन विभाग के सिस्टम को जगाने में नाकाम साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर रखे हैं, लेकिन प्रदेश में इन मौत के सौदागरों को थामने के बजाय सिस्टम लापरवाह बना हुआ है।

विभाग के ही आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे जनता की सुरक्षा को ताक पर रखकर सड़कों को असुरक्षित बनाया जा रहा है। पिछले 12 दिनों में ही विभिन्न आरटीओ और डीटीओ क्षेत्रों से 38,222 ओवरलोड वाहन ई रवन्ना जनरेट होने के बाद भी धड़ल्ले से सड़कों से गुजरे। 200 से अधिक परिवहन निरीक्षकों ने इनमें से 721 वाहनों पर ही कार्रवाई की यानी 37,501 ओवरलोड वाहन बिना कार्रवाई के निकल गए। *(रा.प., 24.06.26)*

**उपभोक्ता फैसले**

### कोल्ड ड्रिंक में मिली गंदगी, कोका-कोला कंपनी पर लगा जुर्माना

जिला उपभोक्ता आयोग, जैसलमेर में तुषार पुरोहित ने कोका-कोला कंपनी एवं शिवम मार्केटिंग के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। मामले के अनुसार परिवादी तुषार पुरोहित ने 16 जुलाई 2025 को शिवम मार्केटिंग से 810 रुपए में कोल्ड ड्रिंक ब्रांड माजा का कार्टन खरीदा था। उन्हें कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल में प्लास्टिक का टुकड़ा और गंदगी नजर आई। इस पर तुषार पुरोहित ने 20 अगस्त 2025 को कोका-कोला कंपनी एवं शिवम मार्केटिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में कोल्ड ड्रिंक ब्रांड माजा की पैक बोतल में प्लास्टिक का टुकड़ा व गंदगी के आरोप को सही पाया गया।

मामले की सुनवाई पर कंपनी की ओर से कहा गया कि जूस को बोतल में भरने का पूरा प्रोसेस ऑटोमैटिक होता है। कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए यह परिवाद दिया गया है। आयोग ने कंपनी की ओर से दी गई इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि इतनी बड़ी और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनी होने के बावजूद पीने योग्य उत्पाद में ऐसा होना गंभीर लापरवाही है।

उपभोक्ता आयोग ने कोका-कोला कंपनी पर ढाई लाख रुपए की पैनल्टी लगाई और आदेश दिए कि इसमें से तुषार पुरोहित को 50 हजार रुपए दिए जाए, बाकी 2 लाख रुपए 'राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष' में जमा कराए जाएं।

*(दै.भा., 16.04.26)*

### बैंक लॉकर के किराए की राशि ब्याज सहित लौटाएं

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर (तृतीय) में मंजरी अतरौलिया ने भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रपति मैदान शाखा के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। उनके अधिवक्ता ने बताया कि परिवादी का उनकी माता के साथ बैंक में संयुक्त खाता था। माता की मृत्यु के बाद उस खाते को परिवादी के एकल नाम से परिवर्तित कर दिया गया था। परिवादी ने नामिनी होने के नाते अपनी माता के बैंक लॉकर को खोलना चाहा, लेकिन बैंक ने इसकी अनुमति देने से मना कर दिया। दूसरी ओर उनके खाते से वार्षिक लॉकर शुल्क की कटौती जारी रखी। बैंक का तर्क था कि परिवादी लॉकर के लिए नामांकित नहीं है। उन्हें लॉकर न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही खोलने दिया जाएगा।

उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि जब परिवादी ने माता के निधन की सूचना बैंक को दे दी थी तो उनके बचत खाते से शुल्क काटना पूरी तरह गलत है। यह अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। आयोग ने बैंक को आदेश दिया कि वह परिवादी के बचत खाते से वसूली गई राशि 9 फीसदी ब्याज सहित वापस लौटाए, साथ ही कानूनी खर्च और मानसिक संताप की एवज में 11,000 रुपए भी दें। *(रा.प., 08.05.26)*

**राजस्व विभाग ने नियमों में किया बड़ा बदलाव**

## भू-उपयोग परिवर्तन 30 दिन में, ग्रीन एनर्जी को दी प्राथमिकता

राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में बदलने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए समय सीमा 45 से घटाकर 30 दिन कर दी है। राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में आवासीय, कॉमर्शियल, औद्योगिक व संस्थानिक उपयोग के मामलों में संभागीय आयुक्त को भी अधिकार दिए गए हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि छोटे मामलों में तहसीलदार व उपखंड अधिकारी मध्यम मामलों में कलेक्टर और बड़े मामलों में संभागीय आयुक्त या राज्य सरकार अनुमति देगी। इनके स्तर पर 15 दिन में फैसला नहीं होने पर मामला स्वतः कलेक्टर को भेजा जाएगा।

बड़ा बदलाव नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर है। अब सोलर, विंड, बायोमास, बायोगैस, सीएनजी-सीबीजी, हाइड्रो और बैटरी स्टोरेज जैसे सभी प्राजेक्ट एक ही श्रेणी 'रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स' में शामिल होंगे। भू-उपयोगपरिवर्तन शुल्क औद्योगिक दर का मात्र 10 प्रतिशत तय किया गया है। न्यूनतम भूमि सीमा 4 हजार से बढ़ाकर 10 हजार वर्गमीटर कर दी गई है। भू-उपयोग परिवर्तन में दी जा रही छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में केवल एससी-एसटी वर्ग को बिना रास्ते के शपथ-पत्र के आधार पर तहसीलदार स्तर पर कन्वर्जन की अनुमति थी, अब यह सुविधा गैर एससी-एसटी आवेदकों को भी मिलेगी। *(रा.प., 30.04.26)*

**स्त्रोतः** रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

**पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी,** डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.228 2821
फैक्सः 228 2485, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैराबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)